



# ACHIEVERS IAS ACADEMY

## SUMMARY OF THE HINDU FOR BPSK EXAMINATION

### HINDI

DATE

**10/12/2023**

## THE HINDU National

### ➔ एनआईए ने 2 राज्यों में आईएस मॉड्यूल पर कार्रवाई की

एनआईए ने शनिवार को महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक साथ 44 स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए ने इस्लामिक स्टेट (आईएस) के 15 कथित गुर्गों को गिरफ्तार किया है। “हिंसक जिहाद, खिलाफत, आईएसआईएस आदि का रास्ता अपनाते हुए आरोपियों ने देश की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का लक्ष्य रखा था...गिरफ्तार आरोपियों ने खुद को ग्रामीण ठाणे के पदना गांव घोषित किया था 'मुक्त क्षेत्र' और एएल शाम के रूप में। एनआईए ने कहा, वे पट्टा आधार को मजबूत करने की अपनी क्षमता से प्रभावशाली युवा पट्टा को प्रेरित कर रहे थे।

### ➔ बसपा ने सांसद दानिश अली को 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' के आरोप में निलंबित किया

बसपा ने पैटी की नीतियों और विचारधाराओं के विपरीत बार-बार टिप्पणी करने के लिए अमरोहा सीट से अपने सांसद दानिश अली को निलंबित कर दिया।

### ➔ कांग्रेस सांसद के परिसर से बड़ी मात्रा में सामान बरामद होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के परिसरों पर आयकर (आईटी) छापे के दौरान अब तक ₹290 करोड़ नकद बरामद किए गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि उनके कांग्रेस से करीबी रिश्ते हैं, लेकिन कांग्रेस ने खुद को इससे अलग कर लिया है

### ➔ मोरबी ब्रिज मामले: कंपनियों को परिजनों को पेंशन देने को कहा गया

गुजरात उच्च न्यायालय ने मोरबी में ओटेवा समूह को अपने बेटों को खोने वाले परिवारों को आजीवन पेंशन और पीड़ितों की विधवाओं को नौकरियां देने का निर्देश दिया है।

मोरबी पुल ढहने से 141 लोगों की मौत हो गई थी, पुल का प्रबंधन ओरेवा समूह द्वारा किया जा रहा था, जो दीवार घड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में शामिल है।

### ➔ रेलवे ने आपातकालीन कैशलेस उपचार योजना वापस ली

भारतीय रेलवे ने कैशलेस ट्रीटमेंट को वापस ले लिया है. आपातकालीन स्थिति में योजना (सीटीएसई)।

इस योजना के तहत रेलवे द्वारा निर्धारित निजी अस्पताल में आपातकालीन उपचार प्रदान किया गया। यह इलाज रेलवे कर्मियों, कार्यरत और सेवानिवृत्त लोगों के लिए उपलब्ध था।

रेलवे ने हवाला दिया कि देश भर में कार्यरत कई रेलवे अस्पतालों द्वारा चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

### ➔ चार साल बाद, सीएए को इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार से राजनीतिक मंजूरी का इंतजार है

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 में पारित किया गया था, लेकिन इसे अभी भी लागू किया जाना बाकी है। कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने के लिए जिम्मेदार संसदीय स्थायी समिति को हाल ही में अपना नौवां विस्तार मिला है और इसे 2024 में लागू किया जाएगा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में विस्थापित छह समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन को नागरिकता दी गई।

इस कृत्य पर पूरे देश में भारी हंगामा हुआ था।



Orchid Mall, Boring Road, (Opps.- A. N. College) Patna-800001

+91 8434931877, +91 7250667974



www.achieversiaspatna.co.in

## ➔ काम से बर्खास्तगी पर महिला की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या किसी महिला को अपने व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज पर अपने माता-पिता के घर का पता अपने निवास स्थान के रूप में रखने के बजाय अपने वैवाहिक घर के पते के रूप में रखने के लिए बर्खास्त किया जा सकता है। याचिका पर तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी।

याचिकाकर्ता धमंती नेल को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि उनके पहचान पत्र में उनके माता-पिता का घर दिखाया गया था।

## World

## ➔ इजराइल ने दक्षिण समेत गाजा पर बमबारी जारी रखी है

शुक्रवार को गाजा में युद्धविराम के प्रस्ताव को अमेरिका ने वीटो कर दिया। सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्य मानवीय युद्धविराम के पक्ष में थे, अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जबकि ब्रिटेन अनुपस्थित रहा। यूएनएससी के 15 सदस्यों में से इस प्रस्ताव पर 13-1 वोट पड़े।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बताया कि गाजा मानवीय सहायता प्रणाली के साथ "ब्रेकिंग पॉइंट" पर है और इसके पूरी तरह ध्वस्त होने का खतरा है।

इजराइल की बमबारी अधिक तीव्र, निरंतर और व्यापक हो गई है।

सीमाएँ बंद होने से नागरिकों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और मरने वालों की संख्या 17400 से अधिक हो गई है।

## ➔ यूरोपीय संघ ने एआई मॉडल को विनियमित करने के लिए नियमों का मसौदा तैयार करने के तरीके पर एक समझौता किया है।

यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों ने चैटजीपीटी जैसे एआई) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मॉडल के विनियमन के संबंध में शुक्रवार को एक समझौता किया। 36 घंटे के विनियमन के बाद "एआई अधिनियम" को अंतिम रूप दिया गया। बातचीत में इस बात पर सहमति बनी कि यूरोप में एआई का उपयोग कैसे किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में नवाचारों को नुकसान नहीं होगा और न ही भविष्य के यूरोपीय एआई चैंपियन की संभावनाओं को नुकसान होगा।

## ➔ मनीला ने बीजिंग पर उसकी नावों पर पानी की बौछार करने का आरोप लगाया है

फिलीपींस ने शनिवार को चीनी तट रक्षक पर स्कारबोरो शोल के पास एक शिपिंग नाव को ईंधन और खाद्य आपूर्ति पहुंचाने वाली तीन सरकारी नौकाओं को "बाधित" करने के लिए पानी का उपयोग करने का आरोप लगाया है।

स्कोरोबोरो शोल चीनी नियंत्रण में है।



Orchid Mall, Boring Road, (Opps.- A. N. College) Patna-800001

+91 8434931877, +91 7250667974



www.achieversiaspatna.co.in

## सामान्य प्रश्न

### ➔ 1. मिचौंगने इतनी अधिक वर्षा क्यों की?

5 दिसंबर को, चक्रवात मिचौंग ने आंध्र प्रदेश में बापटला पर दस्तक दी।

इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसने तमिलनाडु के उत्तर में भारी वर्षा की।

### कैसे बना चक्रवाती तूफान?

29 नवंबर को, आईएमडी ने बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव वाले क्षेत्र की पहचान की। इसके 30 नवंबर को डिप्रेसन, 2 दिसंबर को डीप डिप्रेसन और 3 दिसंबर को चक्रवाती तूफान बनने की आशंका थी। आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि सिस्टम आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ेगा और भारी बारिश करेगा। इसे 5 दिसंबर को नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच टकराना था। यह 2 दिसंबर को चेन्नई के 400 किमी अंदर आया था। इससे भारी बारिश हुई, 80 किमी/घंटा तक तेज़ हवाएँ चलीं। 25 घंटे के भीतर 150 मिमी बारिश हुई।

भारी बारिश के कारण चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

चक्रवात मिचौंग ने 5 दिसंबर को 12:30 बजे बप्ताला में दस्तक दी। यह 11 किमी/घंटा की गति से उत्तर की ओर चला गया। 6 दिसंबर को शाम 6 बजे तक चक्रवात पूरी तरह से शांत हो गया था।

### ट्रॉपिकल चक्रवात



### ➔ 2. पीवीटीजीको विशेषपैकेज का क्या मतलब है?

पीवीटीजी - विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

6 दिसंबर को, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने राज्यसभा में अपने जवाब में कहा कि पीवीटीजी की आबादी में कोई गिरावट नहीं हुई है। इसमें भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा प्रदान की गई जानकारी का हवाला दिया गया।

एक संसदीय समिति ने पहले बताया था कि कम से कम नौ राज्यों में पीवीटीजी की जनसंख्या कम से कम 40% कम हो गई है।

### पीवीटीजी कौन हैं?

प्रारंभ में आदिम जनजातीय समूह के रूप में जाने जाने वाले, पीवीटीजी को जनजातीय समुदायों के रूप में परिभाषित किया गया है जो या तो घटती या स्थिर जनसंख्या, पूर्व कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग, आर्थिक पिछड़ापन, कम साक्षरता आदि दर्शाते हैं। वे देश के कुछ सबसे दुर्गम क्षेत्रों में रहते पाए जाते हैं।

ऐसे 75 समूह हैं जो 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। ओडिशा (15), आंध्र प्रदेश (12), बिहार और झारखंड (9), आंध्र प्रदेश (7), तमिलनाडु (6), केरल (5) आदि। केके मिश्रा की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

2001 की जनगणना के अनुसार पीवीटीजी की कुल जनसंख्या 27 लाख थी।



Orchid Mall, Boring Road, (Opps.- A. N. College) Patna-800001

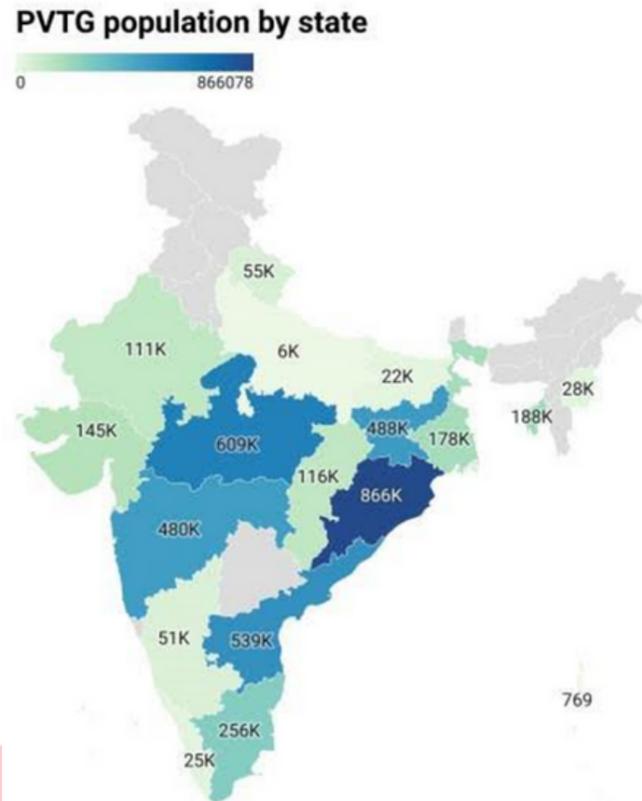
+91 8434931877, +91 7250667974



www.achieversiaspatna.co.in

## ➔ पीएम जनमन का उद्देश्य क्या है?

इस साल की शुरुआत में पीएम द्वारा पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा के बाद कैबिनेट ने हाल ही में ₹ 24000 करोड़ के प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान को मंजूरी दी। मिशन के तहत उन्हें सड़क, मोबाइल फोन, बिजली, घर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।



## ➔ क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं?

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बीयर्सू (एनसीआरबी) द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 की तुलना में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% की वृद्धि हुई है। 2022 में करीब 4.45 लाख अपराध संबंधी घटनाएं दर्ज की गईं।

### अपराध की प्रकृति

अधिकांश अपराध पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा किए गए (31.4%), महिलाओं का अपहरण और अपहरण (19.2%), महिलाओं पर उनकी शील भंग करने के इरादे से हमला (18.7%), और बलात्कार (7.1%)। इसके अलावा दहेज निषेध के तहत 13,479 मामले दर्ज किए गए।

### दिल्ली में हिंसा की दर सबसे ज्यादा है.

कई लोग बताते हैं कि इसके बढ़ने के पीछे पितृसत्तात्मक रवैया और 'सोशल मीडिया पर महिला विरोधी सामग्री', महिलाओं में शिक्षा की कमी आदि मुख्य कारण हैं।

### महिला सुरक्षा के प्रमुख कानून

अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956; दहेजनिषेध अधिनियम, 1961; (सती) अधिनियम, 1987 आयोग; घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013; महिलाओं का अशोभनीय प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986; महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कुछ प्रमुख महिला केंद्रित अधिनियम हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि इनके कार्यान्वयन में धीमी न्याय प्रणाली और पुलिस द्वारा घटिया जांच की दोहरी समस्या का सामना करना पड़ता है।